भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2672
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पारम्परिक जल स्रोतों की स्थिति

2672. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के रामटेक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों में तालाब, छोटे जलाशयों, नहरों और कुओं जैसे पारम्परिक जल स्त्रोत वर्षों से उपेक्षित स्थिति में हैं, जिनमें भारी मात्रा में गाद भर गई है। और वे सिंचाई और जल संचयन के लिए अनुपयोगी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा रामटेक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मनरेगा/अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत इन जल निकायों के पुनरुद्धार , गहरा किए जाने, गाद निकालने और संरचनात्मक सुधार के लिए कोई विशेष कार्यक्रम या अभियान चलाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो रामटेक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने गांवों में विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कार्य किए गए हैं; और

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उक्त हेतु कुल कितने श्रम दिवस सृजित किए गए हैं और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें बॉटम अप आयोजना

दृष्टिकोण अपनाया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए गए कार्यों की सूची में से कार्यों की पहचान, अनुमोदन और प्राथमिकता तय की जाती है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ग्राम सभा में उनकी अनुशंसा की जाती है। तदनुसार , मांग के अनुसार पंचायत द्वारा कार्यों को स्वीकृत और उन्हें शुरु किया जाता है।

(ग) से (ङ): जल निकायों को गहरा खोदना , गाद निकालने और संरचनात्मक सुधार जैसे कार्य महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यकलापों के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, रामटेक लोकसभा क्षेत्र के 65 गाँवों में, जल निकायों को गहरा खोदने , गाद निकालने और संरचनात्मक सुधार जैसे कार्य किए गए हैं। इन कार्यों पर कुल 3,60,481 श्रम दिवस सृजित हुए और 7,61,85,837 रुपये का व्यय हुआ।

*****